

## विज्ञासि

### मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के अन्तर्गत मध्यस्थता केन्द्र संचालित है। माननीय जनपद न्यायाधीश, बस्ती के आदेश के अनुक्रम में उक्त प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के अनुसार उक्त केन्द्र में मध्यस्थ को नियुक्त किया जाना है। जिसके लिए निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं:-

- 1- ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;
- 2- रोवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश;
- 3- ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

आवेदकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

आवेदक उपरोक्त नियमावली की अनुसूची-एक (संलग्न) में दर्शाए गए आवेदन प्रारूप पर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के कार्यालय में दिनांक 20-03-2024 की सायं 4 बजे तक प्राप्त करा सकते हैं।

दिनांक:-06/03/2024

(रजनीश कुमार मिश्र)  
अपर जिला जज / सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
बस्ती।

पत्रक: २३९/जिविंस०प्रा०, बस्ती दिनांक:- 06 मार्च, 2024

प्राप्तिलिपि:-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- राजाध्यक्ष सूचना निदेशक, बस्ती को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त विज्ञासि को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में शुल्क विज्ञासि प्रकाशित कराना सुनिश्चित करे एवं दिजापन की पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
- 3- नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वह जनपद न्यायालय, बस्ती एवं माठ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 4- अध्यक्ष / सचिव सिविल बार एसोसिएशन, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिवक्तागण के मध्य इस सूचना को परिचालित करावेंगे।
- 5- अध्यक्ष / सचिव यंग बार एसोसिएशन, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिवक्तागण के मध्य इस सूचना को परिचालित करावेंगे।
- 6- अध्यक्ष / सचिव कमिश्नर बार एसोसिएशन, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिवक्तागण के मध्य इस सूचना को परिचालित करावेंगे।
- ✓ केन्द्रीय नाजिर, जिला न्यायालय, बस्ती को न्यायालय के सभी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
- 8- नाजिर सदर, जिला कलेक्ट्रेट, बस्ती को जिला मुख्यालय पर स्थित सभी सरकारी भवनों तथा समस्त लहरील भवनों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 06/03/2024

*रजनीश कुमार मिश्र*  
०६।०३।२४  
(रजनीश कुमार मिश्र)  
अपर जिला जज / सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
बस्ती।

**अनुसूची-एक**  
**मध्यस्थता और सुलह केन्द्र**  
**(जिला )**  
**(मध्यस्थ के रूप में पैनल में समिलित किये जाने के लिए आवेदन)**

1. नामः
2. पिता का नामः
3. पता:  
(क) कार्यालयः  
(ख) निवासः
4. दूरभाष संख्या:  
(क) कार्यालयः  
(ख) निवासः
5. मोबाइल संख्या:  
(क) कार्यालयः  
(ख) निवासः
6. ई-मेल आईडीः
7. शैक्षणिक अहताएँः
8. व्यावसायिक अहताएँ और अनुभवः
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई होः
10. मध्यस्थता में विशेष अहता या अनुभव, यदि कोई होः
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांकः  
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूँगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षरः

दिनांकः

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।